आप सोच सकते है उन घरों की हालत जहां लोगों को पांच-पांच किलोमीटर दूर एक घड़े पानी के लिए जाना पड़ता है। ऐसे घरों में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हो सकती है। जानवरों से भी बदतर परिस्थिति में वे लोग रह रहे हैं और खासतौर से कमजोर तबके के लोग जिनके लिए पीने के पानी की सुविधा, सिंचाई के लिये पानी की सुविधा छोड़ दीजिये, आज भी उपलब्ध नहीं है।

मैं एक जगह गया जिसका नाम तपो है। तपोवन बुद्ध के समय एक मशहूर वन था जहा पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उस तपोवन में आज एक ब्लेड आफ ग्रास भी नहीं है। यह वहां की स्थिति है। वहां के हरिजन जो पहाड़ों की तलहटी में बसने के लिए चले गये हैं उनके पास पीने के पानी का कोई भी साधन नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरा स्थान था जेठीवन जिसको आज कहते है जेष्ठीवन। वहां भी मैंने इसी प्रकार की परिस्थिति देखी। वहां पर ऋषि-मुनि तपस्या किया करते थे। सारे इलाके में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं किसी अखबार की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा हूँ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इसके आधार पर यह बात सदन के ध्यान में ला रहा हूं। अभी से बिहार के इन तीनों प्रखण्डों में एक बहुत बड़े भूभाग पर पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर तुरंत इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एक स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा पीने के पानी के अभाव में लोग मरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर इस परिस्थिति में जहां पीने का पानी उपलब्ध नही है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : पद यात्रा में आपको पीने के लिए पानी मिला था या नहीं?

श्री यशवंत सिन्हा : पीने का पानी नहीं मिला था, हमें लोगों के आंसू मिले थे यही मिला था। मैं यह कह रहा था कि अगर तुरंत इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो एक बहुत ही विकराल स्थिति पैदा होगी मुझे इस बात का ताज्जुब है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें जो वर्षों से चिन्ता व्यक्त करती रही हैं कि नक्सलवाद की जो समस्या है, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। वह सोती रही है और उनके इलाके में जहां आज लोग हिंसा पर उतारु हैं वहां पर भी इतनी गम्भीर समस्या का समाधान नहीं ढूंढा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल उस इलाके में न केवल बिहार में बल्कि देश के उन सारे गाँवों में जहां खास कर के गरीब तबकों और कमजोर तबकों के लोग रहते हैं, वहां पीने के पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए और कागजों पर आंकड़ों के लिए नहीं, सचमुच में जमीन पर पीने के पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए क्योंकि सरकारी आंकड़े जो हैं वह बिलकुल फ्राड है, फरेब हैं उनका कहीं कोई तालमेल नहीं है जो जमीन पर सच्चाई है, उससे। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सिन्हा जी ने जो सवाल उठाया है मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और हिन्दुस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया है ड्रिंकिंग वाटर टू ईच एंड एवरी सिटीज़न आफ इण्डिया उसको तुरंत इम्पलीमेंट किया जाए, खास कर के पहाड़ी इलाकों में।

Need for Immediate Commissioning of Kadvan Reservoir Project

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत भारी दिल से इस सवाल को तीसरी बार इस सदन में उठा रहा हूं। बिहार के साथ जितनी ज्यादती केन्द्रीय सरकार की कुनीतियों के चलते हो रही है वह तो अलग है मिनरल्स की लूट, खनिजों की लूट, यह तो कानूनी ढंग से जारी है लेकिन जो बिहार का पश्चिमी इलाका था, आज भी वह नेक्सलाइट लोगों का केन्द्र बिंदु बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है। इस इलाके में इन गतिविधियों में इज़ाफा करने वाली भारत सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की है। पश्चिम बिहार के 6 जिले भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और पटना मरुभूमि में तबदील हो जाने वाले है। अभी तीन हमले बिहार के इस अंचल पर हुए हैं। 115 वर्ष से सोन नदी के पानी पर एकाधिकार था और इन 6 जिलों की सिंचाई होती थी सोन नहर इस देश की सब से पुरानी नहरों में से थी और इन 6 जिलों की भूमि की सिंचाई इसके पानी से होती थी और यह 6 जिले बिहार का अन्न का भंडार माने जाते थे। यह 6 जिले बाकी 15 जिलों को खिलाते थे अन्न के मामले में। आज कदवन योजना जो हमारी अन्तिम आशा थी, भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय ने हमारी आशा को धूमिल कर दिया है और इस कदवन परियोजना को रद्द कर दिया है। हमारी आशाओं को धूमिल कर दिया है।

श्री राम अवधेश सिंह]

इस इलाके पर तीन हमले हुए हैं। सोन आयोग बनाया गया था। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में बिजली के बंटवारे के लिए आयोग बना था। उस आयोग ने अपना काम भी नहीं किया और जो उसकी रिपोर्ट दी उसको कार्यान्वित भी नही कराया। केन्द्रीय सरकार ने उसको पिछले साल भंग कर दिया अगस्त 88 में। यह एक हमला था। पानी के बंटवारे के बारे में दो राज्यों के बारे मे। फिर रेहन डेम जलाशय परियोजना का समझौता हुआ था। उसके अनुसार बिजली उत्तर प्रदेश को जाएगी और पानी बिहार को जाएगा। उसमें 6 टरबाइन थे और एक टरबाइन पर 50 मैगावाट बिजली बनती है और तीन हजार क्यूसेक ५ ? एक टरबाइन से गिरता है। नतीजा यह होता था कि शुरु में हमारे बिहार से आपत्ति उठाई गई कि बिजली में जहां जहां भी देश में बंटवारा हुआ है चाहे डी.वी.सी. में हुआ हो, बंगाल और बिहार का बंटवारा हुआ हो और कावेरी नदी में कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ है, सतलुज में हरियाणा और पंजाब में हुआ है, तो फिर बिहार में जो पनबिजली बनती है रेहन नदी पर, उसमे उत्तर प्रदेश और बिहार मे क्यो नहीं बंटवारा होगा? तीन सौ मैगावाट बिजली बनती है, उसमें हमारी मांग थी कि डेढ़ सौ मैगावाट बिजली बिहार को मिले और डेढ़ सौ मैगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिले। हालांकि सिंगरौली प्रोजेक्ट से करीब 16 से 18 हजार मैगावाट बिजली बनती है **(व्यवधान)** आपको मालूम नहीं है 1600 नहीं, 16 हजार मैगावाट बिजली बनती है, ऊर्जा मन्त्री जी बैठे हैं। मैं फिगर्ज़ से बोलता हूँ, ऐसे थोड़ा ही बोल रहा हूँ, तो उसमें जो भी गलत समझौता हो गया वह चाबुक के बल पर हमारे कमजोर मुख्य मन्त्री अब्दुल गफ्फूर खान से समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये गये कि पानी बिहार को और पनबिजली उत्तर प्रदेश को जायेगी। नतीजा यह हुआ कि आज रिहन्द जलाशय से पानी नीचे गिरकर पनबिजली बनकर आता है और उस पनबिजली को भी चोरी चोरी से उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहां डाइवर्ट करके सिंगरौली के ताप बिजलीघरों में ले जाती है। रिहन्द डैम से सिंचाई का जो जल मिलता था उसके बद होने के कारण नतीजा यह हो रहा है कि 115 वर्ष पुराना नहरों का जो जाल था जिससे सिंचाई की व्यवस्था थी वह पूरी तरह से भंग हो गया है। फिर तो बिहार सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एक योजना केन्द्र को दी कि कदवन में एक जगह पर सोन नदी पर एक बड़ा जलाशय बनाया जाये ताकि बरसात में जो फालतू पानी आता है उसको रोक कर गर्मी के दिनों में या बरसात खत्म होने पर उसका उपयोग किया जाये। रिहन्द की जो बेईमानी थी, इससे उसकी कमी की जा सकती थी लेकिन उसको भी केन्द्र सरकार ने 4 रोज पहले रद्द कर दिया और कहा कि अब यह कदवन जलाशय की परियोजना नहीं लागू की जायेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): कृपया समाप्त कीजिए। देखिए यह स्पेशल मेंशन है। आपके सात मिनट हो गये हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : समाप्त करने की बात नहीं है, यह तो लड़ने की बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। हमारे 6 जिलों के घरों में चूल्हे बंद हो जायेंगे और ये 6 जिले, जो बिहार के अन्न भंडार थे, जल्दी ही मरुभूमि में तब्दील हो जायेंगे। इसलिए इस बात को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान्यवर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे साथ कितनी बेईमानी हो रही है। आसाम को पैट्रोलियम पर रायल्टी भारत सरकार देती है, 25 परसेंट और कोयले पर बिहार सरकार को रायल्टी देती है 1 परसेंट। आप बताईये यह बर्दाश्त होने की चीज है। लेकिन इसका जवाब सरकार नहीं देती है। मैंने उस दिन... **(व्यवधान)** मेरी बात सुनी जाए, हंगामा किया था। मैंने कहा था इस पर जवाब दें। इसी तरह का सवाल था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया तो उस दिन कहा गया कि हाथ के हाथ जवाब आ जाएगा, तीन सप्ताह में जवाब आ जाएगा और फिर तीन सप्ताह से ज्यादा हो गये, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री लोग यहां पर मौजूद हैं — ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं — ऊर्जा मन्त्री जी ध्यान दीजिएगा सरकार की कलेक्टिव रेसपांसिब्लिटी पर और आप यहां बैठे हुए हैं, मेरी बात सुनिये और जवाब दीजिए कि संसाधन मंत्रालय ने जो कदवन परियोजना को रद्द कर दिया है और बिहार को मरुभूमि में तबदील करने की योजना बनाई है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? आप बोलिये क्योंकि उसमें आप हमको हर तरह से मार रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : राम अवधेश सिंह जी, अब समाप्त करिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं समाप्त नहीं करूंगा। आज तो मैं अवश्य बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): हर दिन का बकाया तो आज पूरा नहीं होगा ना । आप एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर, आप मेरा दर्द समझिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): समझ गये...**(व्यवधान)** सारा हाऊस आपका दर्द समझ रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): गवर्नमेंट भी इनका दर्द नहीं समझती और न आप समझ रहे है।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई साधारण सवाल नहीं है। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट प्लेस हो, इसके लिए सदन मे हंगामा हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार की बेवकूफी से, बदनीयती से, कुनीति से बिहार के छह जिले मरुभूमि में बदलने वाले हैं और भारत सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है। तो हम लोग इस सदन को नहीं चलने देंगे और यहां की कार्यवाही को हम लोग अवरुद्ध करेंगे। मैं आज कार्यवाही अवरुद्ध करना चाहता हूं — यह कार्यवाही आगे नहीं चलेगी ताकि सरकार सुने। पिछली दफा सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि हम तीन सप्ताह में इसके बारे में करेंगे। तो जवाब पाजिटिव होना चाहिए, हमारी राहत का काम होना चाहिए, लेकिन उलटा कर दिया। सोन आयोग को रद्द कर दिया, कदवन परियोजना को रद्द कर दिया और हम लोग यहां चुपचाप बैठ कर दस्तखत करके भत्ता लेकर जायें—इसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम इस बात को कहने आये हैं और मैं सदन को आज चलने नहीं दूंगा और वह इसलिए कि हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, हमारे चूल्हे की आग भारत सरकार द्वारा बुझाई जा रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): आप क्या बात कर रहे हैं?... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आप अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: सुकुल जी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह: मै भारत सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जो कदवन परियोजना को रद्द करने का एलान किया गया है, उसको तत्काल लागू किया जाए और रिहंद सागर परियोजना तैयार होने के साथ-साथ यह योजना तैयार हो जाए। जो जल की हमारी कमी हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति कदवन परियोजना से हो जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि यह बारूद में आग लगाने के बराबर होगा और यह बारूद के ढेर में केवल यही मुद्दा है — पानी में बेईमानी के सवाल को लेकर देवी लाल जी ने जब हरियाणा में आग लगाई थी और पानी में बेईमानी ही नहीं, हमारे साथ रायल्टी में बेईमानी है, कोयले में बेईमानी, परियोजना की आवंटन राशि में बेईमानी है। किसी चीज में ऐसा नहीं है कि बिहार को हिस्सा मिले। पूरे मुल्क की 45 प्रतिशत खनिज सम्पदा बिहार में है — 45 प्रतिशत और सारे देश की 55 प्रतिशत है, लेकिन हमारा प्रदेश सब से गरीब प्रदेश है।

तो मैं यह चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर भी हमको मिले। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, मान्यवर, आपको मालूम होगा कि एक लाख अस्सी हजार करोड़ की रकम खर्च होने वाली है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): काफी समय हो गया है।

श्री राम अवधेश सिंह: यह उसी में आता है क्योंकि यह कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): काफी समय हो गया है। देखिये अब तो 12 मिनट हो गये हैं।

श्री राम अवधेश सिंह: मुझे दो-तीन मिनट समय और दीजिए। एक लाख 80 हजार करोड़ सातवीं योजना में जो खर्च हो रहा है उसमें हमारी मांग थी और है कि साढ़े दस फीसदी बिहार की आबादी है तो उसके हिसाब से 18 हजार 9 सौ करोड़ रुपया हमको हिस्सा दे दो, हम 11 परसेंट नहीं मांगते हैं 12 फीसदी नहीं मांगते हैं, हम केवल साढ़े दस फीसदी मांगते हैं तो साढ़े दस फीसदी जितनी आबादी है तो हमको 18 हजार 9 सौ करोड़ रुपये हिस्सा मिलता लेकिन हमको दिया गया 5 हजार 1 सौ करोड़। मतलब पौने तीन परसेंट हमारे डिमांड और आवश्यकता का दिया गया और हमारे यहां से 45

[श्री राम अवधेश सिंह]

फीसदी लोहा, कोयला, तांबा, अबरक, मैगनीज़, यूरेनियम ला करके सारे देश को आप सम्पन्न बनाते हैं और हमारे सूबे को गरीब बना रहे हैं। उसको लूट रहे हैं और शोषण कर रहे हैं यह बर्दाश्त के बाहर है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यह जो दो मंत्री जी यहां पर बैठे हैं यह जवाब दें कि कदवन परियोजना के बारे में क्या होगा और कोइलकारो परियोजना के बारे में यहां मंत्री जी हम से बोल चुके हैं कि यह तुरन्त लागू होगी और वह दस साल से लंबित है और यह अभी तीन-चार सौ करोड़ रुपये की परियोजना थी वह एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है फिर भी उस पर काम शुरु नहीं हो रहा है, इन दोनों के बारे में यहां मंत्री जी जवाब दें? नहीं तो मैं तो बैठूंगा नहीं और मैं बोलता रहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आपने कहा था कि दो मिनट समय और दे दीजिए तब मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए अब आप समाप्त करिए।

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर, मैं जवाब चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): जवाब देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह: यह दोनों मंत्री हैं, एक तो ऊर्जा से संबंधित हैं। कोइलकारो के बारे में जवाब दीजिए। इनका जो अफसर है पावर विभाग का और पनबिजली विभाग का, ये लोग इनको उल्टा-सीधा पढ़ा देते हैं मंत्री जी का अगर मन भी होगा तो भी ट्रैक्नीकल या इधर-उधर का कह देते हैं। तो यह कौन बात के मंत्री है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आप समाप्त करिए।

श्री राम अवधेश सिंह: यह मंत्री जी को उल्टा-सीधा समझा देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): राम अवधेश जी अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह: अच्छा, स्थान ग्रहण करने से पहले मैं सरकार से जवाब चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा (बिहार): हम भी राम अवधेश जी से पूरी तरह सहमत हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आप कृपया स्थान ग्रहण करें। देखिए, स्पेशल मेंशन में आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया ... **(व्यवधान)** देखिए जितना समय आपने कहा था उससे तिगुना समय दे दिया गया। स्पेशल मेंशन में नियम यह है और जो परिपाटी है वह यह है कि स्पेशल मेंशन माननीय सदस्य उठाते हैं और उसके बाद विभागीय मंत्री उसका लिखकर उत्तर देते हैं। तो सरकार के मंत्रियों ने आपके स्पेशल मेंशन को सुन लिया है और वह उसका उत्तर देंगे। अब श्री सुरेश कलमाडी ...**(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: दो मिनट ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अब राम अवधेश जी जो कहते हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह: *

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Madam, ... *(Interruptions)*

श्री पशुपति नाथ सुकुल: इनको नेम कीजिए और इनको सदन से बाहर कीजिए।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, I am on a point of order. My point of order is that it has been very specifically mentioned that this is a privilege that we are getting in this House. The Member of the other House do not get this privilege. But we should not misuse this privilege. You have said that a maximum of only three or four minutes are allowed. If one continues for 15 minutes, the Government may come out with a

*Not recorded

proposal and disallow it. This thing should not be allowed by us.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): श्री राम अवधेश सिंह जी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी भावनाओं से सदन अवगत् हो गया है।

श्री राम अवधेश सिंह: मंत्री जी यहां बैठे हैं यह जवाब दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): कलमाडी जी, एक मिनिट, मंत्री जी उत्तर देगे।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री(श्री कल्पनाथ राय): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कोइलकारो परियोजना के संबंध में प्रश्न उठाया है, मै लिखित उत्तर इनके पास भेज दूंगा।

श्री राम अवधेश सिंह: क्या कहा?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): यह जो आपने प्रश्न उठाया है। इसका उत्तर आपको देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह: उत्तर नहीं। यह बताएं कि लागू होगा कि नहीं होगा और होगा तो कब होगा? यह तो बेवकूफ बनाने वाला उत्तर हुआ। आप सदन में उत्तर दीजिए। इस मंच पर उत्तर दीजिए कि क्या करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कोइलकारो प्रोजेक्ट सरकार के विचाराधीन है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने टेक्नो-इकोनोमिक क्लीयरेन्स दे दिया है। अब यह पी. आई. बी. के सामने विचाराधीन है और जब यह पी. आई. बी. से क्लीयर होगा तभी केबिनेट के सामने जाएगा। जो प्रोसीजर है, मान्यवर, वही तो होगा।

श्री राम अवधेश सिंह: चार महीने से यही कह रहे हैं। ... (**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): राम अवधेश सिंह जी, अब आप बैठ जाइए। आपको उत्तर दे दिया गया है। दूसरे माननीय सदस्यों को अपना स्पेशल मेंशन कहने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... सारे सदस्य आपसे सहमत हैं।

श्री राम अवधेश सिंह: मान्यवर, यह बर्दाश्त के बाहर है। आज जिसके घर में चूल्हे मे आग बुझ रही है, उसके मन की आग को आप समझ सकते हैं कि कितनी आग है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश कलमाडी: आप कृपा करो, राम अवधेश सिंह जी।

श्री राम अवधेश सिंह: आप लोग कृपा करो न हम पर।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): मंत्री जी ने आपको जवाब दे दिया है। दूसरे सदस्यों को भी कुछ कहने दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह: आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आखिरी बात कह कर बैठूंगा। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप सरकार को निर्देश दीजिए। मै यह सवाल बार-बार उठाता रहा हूँ तीन बार उठा चुका हूँ और इसका कोई ठोस जवाब नहीं आया, कोइलकारो के बारे मे भी नहीं आया और कदवन परियोजना के बारे में भी नहीं आया। तो मै लाचार होकर यह अंतिम काम कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप उस कुर्सी से निर्देश दीजिए सरकार को कि कदवन परियोजना और कोइलकारो परियोजना कब चालू होगी। इसका पाँच रोज के अंदर जवाब दिया जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री राम अवधेश जी ने जो प्रश्न उठाया था, उसका ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय जी ने सदन में एक अंतरिम उत्तर दिया है। अब पुनः श्री राम अवधेश जी ने उनका ध्यान आकर्षित किया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे कृपया विस्तृत उत्तर भिजवा दें जिससे कि श्री राम अवधेश जी को संतोष हो जाए।

श्री राम अवधेश सिंह: लागू हो जाए, यह बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप विस्तृत उत्तर दीजिए। आप कहेंगे कि यह टैक्नीकल गड़बड़ी है, वह टैक्नीकल गड़बड़ी है — यह बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम

[श्री राम अवधेश सिंह]

सुनना चाहते हैं कि कोइलकारो परियोजना लागू हो । ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम रसूल मट्टू: राम अवधेश जी, अब कृपा कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): राम अवधेश जी, आपने खुद कहा कि पांच दिन के बाद जवाब दें। अब आप अपनी बात को क्यों कंट्राडिक्ट करते हैं? श्री सुरेश कलमाडी, आप अपना स्पेशल मेंशन रखिए ।

श्री राम अवधेश सिंह: महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूं और वाक आउट करता हूं।

[इस समय माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए]

Need to Provide Air-Link to Various Tourist Spots in Maharashtra

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Sir, keeping in view the tradition of this House, I shall not make my Special Mention for more than three minutes. My Special Mention relates to the very poor air link of various tourist spots in Maharashtra. Sir, 50 per cent of the international traffic comes to Bombay, but once the passengers come to Bombay, they do not have flights to go to various tourists spots, specially like Aurangabad. Sir, you are aware that 80 per cent of this country's caves which are listed in the World Heritage Book are mostly in and around Aurangabad, and many a foreign tourist wants to go to Aurangabad, but because of very poor air link between Bombay and Aurangabad and Delhi and Aurangabad, many tourists cannot go there.

Sir, the Aurangabad airport needs to be lengthened so that direct charter flights can land at Aurangabad too. We have received a lot of demands from various foreign charters to land directly at Aurangabad. But that is not possible till the runway is extended. Sir, there are some other airports like Ratnagiri, Jalgaum and Kolhapur which have already been commissioned. But, unfortunately, there are no flights operating at these airports. You are aware that Maharashtra has got 700 KMs of coastline, and Ratnagiri is right in the centre of it, and it is unfortunate that no airline has started operating there as yet. We have also Jalgaum airport which is so near to the Ajanta caves. But, unfortunately, that also has not been activated.

Sir, we have requested for a few more airports in Maharashtra. One is at Kudal and that is in the Konkan area. The other is at Shirdi which is a religious place. We have asked for an airport for that. The National Airports Authority has come there and surveyed the area. But they must speed it up. We have also asked for an airport near Ajanta. Sir, also, it is time we thought of an alternative international airport to Bombay. In Bombay, the airport is getting congested. About 50 miles away from Bombay, there should be a spot for an international airport. And you start planning now because it requires quite a few thousand acres...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): If the hon. Member could yield for a minute, as a Member of the National Airports Authority of India, I would like to inform him that we laid the foundation stone for the first phase of expansion of the Bombay international airport. And it is going to be at par with any international airport. There are four different phases in which the airport is going to grow. So, I don't think you will have any complaint in terms of capacity, passenger handling service and every other facility that backs an international airport.

SHRI SURESH KALMADI: What she is talking is about the additional facilities which they are providing at the present airport. My contention is that this airport